विषय- उत्तर प्रदेश के असंगठित कामगार महिलाओं की स्थिति : एक अध्ययन
"उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विशेष संदर्भ में"

प्रस्तावना-

भूमंडलीकरण के इस दौर में असंगठित कामगार महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में हमेशा से अनौपचारिक या परम्परागत क्षेत्र का दबदबा रहा है जिसमें अधिकांशतःस्त्रियाँ स्वरोज़गाररत हैं। इस क्षेत्र में तरह-तरह के बेशुमार उत्पादक, कारोबारी और सेवामूलक व्यवसायों का जाल बिछा रहा है। इन घरेलू-स्थानीय या आंचलिक छोटे-मझोले उद्योग-धन्धों में स्त्रियाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। आज ऐसी अनगिनत रोज़गारदायी उत्पादक इकाइयों, गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों का लोप होता जा रहा है। दोहरी मार पड़ रही है- एक तरफ बाहर से बेरोकटोक जारी भारी मात्रा में सस्ते आयात इनकी क़मर तोड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े प्रौद्योगिकी-प्रधान, पूँजी-सघन और रोज़गारभक्षी विनिर्माण-संयन्त्र, उत्पादन-संकुल या कल-कारख़ाने लग रहे हैं जिनसे खेतीबाड़ी उजड़ रही है, रोज़ी रोटी के पुश्तैनी या बुनियादी स्रोत सूख रहे हैं स्थानीय लोगों या समुदायों का विस्थापन हो रहा है और पर्यावरण का सर्वनाश हो रहा है। बहुमात्र उत्पादन पर टिका कॉरपोरेट-केन्द्रित मॉडल समूल विनाश कर रहा है उस मॉडल का, जो मॉडल 'लोगों द्वारा उत्पादन' पर टिका हुआ है। कुल मिलाकर इन सबके फलस्वरूप अनौद्योगीकरण का भीषण संक्रामक रोग देश-भर में फैला हुआ है जिसकी चपेट में सबसे पहले महिलाएँ आ रही हैं।

कामगार महिलाएँ आज चौराहे पर खड़ी हैं । ज्यादतर महिलाएँ गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित होने के कारण उन्हें सामाजिक, आर्थिक और कई बार तो शारीरिक शोषण का शिकार भी होना पड़ रहा है । महिला कामगार सामाजिक सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, अवकाश, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। आर्थिक विकास के मौजूदा मॉडल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढने के बजाय घट रही है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट बताती है कि सन् 2009-10 और 2011-12 यानी दो वर्ष के अन्दर गांवों में महिला श्रमिकों की संख्या में 90 लाख की कमी आयी है। वैश्वीकरण और बाजार आधारित आर्थिक मॉडल अपनाने के लगभग 20 वर्ष पहले सन् 1972-73 में श्रमशक्ति में महिलाओं का योगदान 32 फीसदी था। उदारीकरण की राह पकडने के 20 वर्ष बाद सन् 2010-11 में यह संख्या घटकर 18 प्रतिशत रह गई। विकास की परिभाषा में औरतों के काम के घंटों में वृद्धि, उनके प्रजनन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक सरकारी नियंत्रण और हिंसा की प्रक्रिया पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है।

समस्या का स्वरुप

कामगार महिलाओं की समस्याओं की तरफ समाजशास्त्रियों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस समस्या का समाजशास्त्रियों ने अपने विचारों से जानने का प्रयास किया कि कामगार महिलाओं की समस्या सैद्धान्तिक तथा व्याहरिक स्तर पर इतने ऊँचे तक पहुँच जाएगी। जनसंख्या की विशालता एवं गतिशीलता के परिणामस्वरुप भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवसायियों के सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याओं का प्रादुर्भाव हो चुका है। जिसमें श्रमिक महिलाएं की समस्या सबसे महत्वपूर्ण एवं विकट हैं।

शोध के उद्देश्य -

80 के दशक के बाद से ही महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और अन्याय पर अनेक प्रकार के अध्ययनों और शोधों ने बौद्धिक जगत में एक केन्द्रीय और अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के अंदर महिलाएं एक अनिवार्य अंग के समान होते हुए भी उनकी स्थिति हमेशा से ही दोयम दर्जे की बनी रही है।

- असंगठित कामगार महिलाओं की अवधारणा एवं स्थिति का अध्ययन करना।
- असंगठित कामगार महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थियों का अध्ययन करना।
- असंगठित कामगार महिलाओं के लिए बने संवैधानिक नियम व कल्याण हेतु कार्य कर रहे विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों का अध्ययन करना।
- असंगठित कामगार महिलाओं की मूलभूत सुविधाएँ जैसे- शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन आदि का अध्ययन करना।

उपकल्पनाएँ –

आजकल शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं, केंद्रीय और राज्य सरकारों, योजना दलों और सुधारकों का ध्यान इतना आकृष्ट करता है जितना कि महिलाओं की समस्याएँ। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण हुआ और वे तिरस्कार व प्रताड़नाओं का शिकार होने लगी। स्त्रियाँ अपने सगे-संबंधियों एवं अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा मारी-पीटी जाने लगी और देखते देखते स्त्रियों पर इस प्रकार के शोषण एवं अत्याचार का प्रभाव इस कदर दिखाई देने लगा कि वे अपने ऊपर हो रही इस

रोजमर्रा कि घरेलू हिंसा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझने लगी और पुरुष इसको अपना अधिकार समझने लगा।

- असंगठित कामगार महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार का भय बना रहता है।
- समाज में पायी जाने वाली सामाजिक-आर्थिक विषमता भी असंगठित कामगार महिलाओं के श्रम के लिए उत्तरदायी है।
- असंगठित कामगार महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, मजदूरी आदि असमानता का व्यवहार किया जाता है।
- असंगठित उद्योगों में कामगार महिलाओं के संरक्षण एवं उत्थान के लिए बने कार्यक्रम अपर्याप्त है। तथा उनकी जानकारी भी नहीं होती है।

शोध प्रविधि-

सामान्य रूप में यदि हम देखें तो स्त्री-पुरुष व्यक्ति शब्द के एक ही उच्चारण हैं पर समाज के विस्तार ने और सभ्यताओं के विकास ने स्त्री और पुरुष दोनों को अलग-अलग खाचों में डाल दिया है .

A: अनुसंधान पद्धति-

मात्रात्मक

तुलनात्मक पद्धति

B: आंकड़े एकत्रित करने के स्त्रोत

प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के स्त्रोत

1.प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा

2.अनुसूची

3.साक्षात्कार

4.सर्वेक्षण

द्वितीय आंकड़े एकत्रित करने की स्रोत

सरकारी एवं गैर सरकारी आंकड़ें

पुस्तक

जर्नल्स

मानचित्र आदि

तथ्य संकलन के उपकरण

अध्ययन के उद्देश्यों अनुसूची का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम उद्योग में लगे असंगठित कामगार महिलाओं की विस्तृत रुपरेखा तैयार की गई। प्रमुख पक्षों का निर्धारण किया गया और उनके आधार पर अन्य श्रमिकों से संबंध स्थापित करते समय इस बात का प्रयास किया गया कि उत्तरदाताओं को स्वतंत्र विचार विमर्श का अवसर मिले। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आए जो भ्रान्तिपूर्ण थे तथा कुछ प्रश्नों के अनेक उत्तर भी प्राप्त हुए। इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर अनुसूची को अन्तिम रुप दिया गया। और इनमें सभी संभाव्य उत्तरों का समावेश किया गया। इस प्रकार संरचित अनुसूची का निर्माण किया गया। अनुसूची से संबद्धित उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय उनकी पारिवारिक स्थिति जनांकिकी स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, मजदूरी, शोषण आदि के समाधान हेतु सरकारी प्रयास आदि का समावेश अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है।

लघु शोध प्रबंध के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण

प्रथम अध्याय - उत्तर प्रदेश की असंगठित कामगार महिलाओं की स्थिति का अध्ययन : वर्तमान सन्दर्भ में

उत्तर प्रदेश आज विकास और प्रगति के तमाम दावों के बावजूद देश की आधी आबादी अपने हालातों से जद्दोजहद करती हुई दिखती है। असंगठित कामगार महिलाओं की दशा अपने ही परिवार में दुःख का जीवन गुजरना पड़ता है। हाशिये की महिलाएं, मजदूर, आदिवासी एवं दलित महिलाओं पर बात करना आज बहुत जरुरी है क्योंकि मजदूर, आदिवासी एवं दलित महिलाओं का एक ऐसा तबका है जो महिलाओं में भी सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों भेदभाव और शोषण का शिकार होती है। महिला सशक्तीकरण के नारों और दावों के बीच निर्भया जैसी घटनाएँ हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति का भयावह चित्र प्रस्तुत करती हैं। नारीवादी आंदोलन के जरिये महिलाओं की मुक्ति की कल्पना की गयी

थी, लेकिन अधिकांश भारतीय महिलाएँ उससे कोसों दूर हैं । शहरों और महानगरों की पढ़ी-लिखी महिलाओं में जागरूकता अवश्य देखी जा रही है । समाज में अपनी उपस्थिति, अधिकारों और समस्याओं को लेकर महिलाएँ मुखरित होने लगी हैं । इन वर्षों में महिलाओं के व्यवहार व परिस्थिति में जो परिवर्तन आया है, क्या वह किसी ठोस बदलाव का सूचक है इस पर विचार करना आवश्यक है ।

द्वितीय अध्याय - असंगठित कामगार महिलाएं : घर एवं बाहर का संघर्ष

श्रम का पितृसत्तात्मक लिंग विभाजन महिलाओं पर दोहरे काम का बोझ डालता है, जिसमें घर के बाहर काम करने के साथ-साथ उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं. और महिलाओं के ऊपर घर के काम के बोझ में इजाफा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राथमिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ-सफाई का निजीकरण हो गया है, या उनमें कटौती हो गई है, और ऐसे में महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसकी भरपाई करें. नवउदारवादी पूंजीवाद के संकट के चलते बुनियादी वस्तुओं के बढ़ते दामों की वजह से, महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि आखिर घर उन्हें ही चलाना होता है.

तृतीय अध्याय - असंगठित कामगार महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं गैर सरकारी योगदान

आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनियां में भारत और यही की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाऐं डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलायें विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्ष पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं। लेकिन आज हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो असंगठित क्षेत्रो से अपने जीवन को सवारने में लगी है तथा कई प्रकार के शोषण की शिकार भी हो रही है .

चतुर्थ अध्याय- असंगठित कामगार महिलाओं की दशा एवं दिशा का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

इस अध्याय में अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सारणी और ग्राफ के माध्यम से किया गया है। शोधार्थी ने विश्लेषण हेतु विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

पंचम अध्याय – निष्कर्ष एवं सुझाव

असंगठित कामगार महिलाओं का जीवन किन-किन समस्याओं से होकर गुजरता है इसका अध्ययन इस शोध में किया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या असंगठित कामगार महिलाओं के समक्ष आजीविका और आजीविका के साधनों की हैं। आज आजीविका के पारंपरिक स्रोतों भूमि, वन, समुद्र, नदी, चरागाह, पशु आदि- खोने से महिलाएं मजदूर बनने को विवश हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और पौष्टिकता की समस्या से पीड़ित हो गई हैं, बल्कि अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकने की क्षमता भी खो देती हैं। विस्थापितों में एक और बेहद कमजोर समूह भूमिहीन विस्थापितों का है, जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं ।